

क्रमांक- 42130479
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल-462003
दूरभाष 2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,
Email ID-cao.eincwrdbpl@gmail.com

भोपाल, दिनांक /11/2018

प्रति,

मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग,
(म0प्र0)

विषय :- ठेकेदार के विरुद्ध निलम्बन/काली सूची में डाले जाने संबंधी आदेश जारी करने
विषयक ।
संदर्भ :- कार्यालयीन पृष्ठांकन क्र. 319/271/ई.टे./2015-16/1850, दिनांक 10.12.2015
एवं पत्र क्रमांक 42130479, दिनांक 27.05.2016

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पृष्ठांकन द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण
विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक IT cell/Reg/87/2015/1004 भोपाल, दिनांक 10.12.2015 एवं
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग का आदेश क्रमांक एफ-17-1/19/बी/2010/392/भोपाल,
दिनांक 03.05.2016 की छायाप्रति पुनः संलग्न प्रेषित हैं ।

उक्त पृष्ठांकित आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि ठेकेदार के विरुद्ध की गयी
कार्यवाही संबंधी आदेश जारी करने के साथ ही वेबसाइट पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
इस हेतु मुख्य अभियन्ताओं को संबंधित वेबसाइट पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड दिये गये हैं ।

किन्तु प्रायः देखने में आया है कि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है,
जिससे कार्य में कठिनाई उत्पन्न होती है ।

अतः पुनः लेख है कि ठेकेदार का पंजीयन निलम्बन/काली सूची में रखने के संबंध
में आदेश प्रसारित करने के साथ ही की गई कार्यवाही वेबसाइट पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित
करें ।

- ~~उत्पल~~ -

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग भोपाल.

भोपाल, दिनांक 14/11/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 42130479


प्रतिलिपि :-

बेव मैनेजर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग की ओर विभागीय
वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

- ~~उत्पल~~ 13.11.18

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग भोपाल. 

"कुशवाहा"

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश निर्माण भवन, प्लॉट क. 27,28 अरंरा हिल्स भोपाल
(केन्द्रीय पंजीयन प्रकोष्ठ)

Website: www.mp.gov.in/pwdmp

e mail : itmppwd@mp.gov.in

पत्र क्रमांक- IT Cell/Reg/87/2015/ 1004

भोपाल, दिनांक, 10/12/15

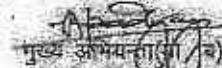
प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
मध्यप्रदेश,

विषय- ठेकेदारों के विरुद्ध निलंबन/काली सूची में डाले जाने संबंधी आदेश जारी करने
विषयक

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता द्वारा किसी भी ठेकेदार के विरुद्ध निलंबन /काली सूची में डाली जाने वाली कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते हैं। ऐसा अनेक प्रकरण में देखने में आया है कि उपरोक्त आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में समय पर नहीं पहुँच पाती है। जिसके कारण ठेकेदारों का नाम निलंबन/काली सूची में डाली जाने वाली प्रक्रिया का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिये विभाग द्वारा आपके विभाग के मुख्य अभियंताओं को एम.पी.ऑनलाइन की पंजीयन व्यवस्था में सीधे एक्सेस हेतु एडमिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किया जा रहा है, जिससे मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार का नाम निलंबन/काली सूची में डालने पर उसी समय एम.पी.ऑनलाइन की पंजीयन व्यवस्था में उक्त एडमिन आई.डी. पासवर्ड (यानि आई.डी. पासवर्ड) दिये जा रहे हैं। कृपया प्राप्त होवे ही पासवर्ड सुविधानुसार परिवर्तित कर लीजियेगा। भविष्य में किये जाने वाले निलंबन/काली सूची में डाले जाने वाली कार्यवाही उपरोक्तानुसार संपादित करें। सॉफ्टवेयर के संबंध में एमपी ऑनलाइन हेल्प नम्बर 9630838436 (श्री राहुल पाठक) है।


मुख्य अभियंता (पंजीयन)
पंजीयन अधिकारी
(केन्द्रीय पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल

सं. क्र. 319/271/ई-से/2015-16/1850


दिनांक: 10/12/15

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य अभियंता की और पालनार्थ, विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।

2. वेब सैलर, परिपालना संचालक, पाईक, भोपाल, की और विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अधिसूचित।

संलग्न
उक्तानुसार


R.K. Khandelwal
G.E. (Proc.)
Link Officer to E-in-C
W.R.D., Bhopal

15/11/14
11
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

240

आदेश

क्रमांक / एफ 17-1/19/बी/2010

भोपाल, दिनांक .05.2016

केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ठेकेदारों के पंजीयन के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक 7882/9671/19/यो भोपाल दिनांक 19.11.1999 के अनुसार ठेकेदारों के पंजीयन के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात शासन के आदेश क्रमांक एफ 17-1/2010/19/बी भोपाल दिनांक 24.03.2015 द्वारा इस संबंध में नवीन निर्देश जारी किये गये हैं। अतः पूर्व में जारी उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 19.11.1999 तत्काल प्रभाव से अधिकमित किया जाता है।
2. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश एफ 17-1/2010/19/बी भोपाल दिनांक 17.08.2011 द्वारा ठेकेदारों के पंजीयन के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिनांक 19.11.1999 को जारी आदेश के संबंध में प्रक्रियात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश को म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-1/बी/19/2010 भोपाल दिनांक 11.05.2015 द्वारा अधिकमित किया गया है।
3. अतः वर्तमान में प्रचलित नियमों के अंतर्गत ठेकेदारों के पंजीयन के विरुद्ध केवल पंजीयन निलंबन अथवा काली सूची में नाम डालने की व्यवस्था है। शासन चाहता है कि यह कार्यवाही निम्नानुसार की जाये।

अ. यह कार्यवाही संबंधित विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। जिसकी विधिवत सूचना संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, योजना एवं बजट (राज्य पंजीकरण अधिकारी) प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग भोपाल को तीन दिवस के अंदर दी जाना होगी। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को संबंधित वेबसाइट पर यूजर आई डी एवं पासवर्ड दिये गये हैं। अतः मुख्य अभियंता ठेकेदार के पंजीयन के विरुद्ध की गई कार्यवाही आदेश जारी करने के साथ ही वेबसाइट पर दर्ज किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित विभाग में मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नहीं है तो यह कार्यवाही उस विभाग की अनुशंसा के आधार पर उस जिले से संबंधित लोक निर्माण विभाग के परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इसकी सूचना राज्य पंजीकरण अधिकारी लोक निर्माण विभाग को दी जाने के अतिरिक्त इसे वेबसाइट पर दर्ज करायेगी। राज्य पंजीकरण अधिकारी संबंधित मुख्य अभियंताओं से सूचना प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेंगे कि तत्संबंधी प्रविष्टि वेबसाइट पर कर दी गई है अन्यथा वे स्वयं उसे तत्काल वेबसाइट पर दर्ज करवायेगे।

ब. मुख्य अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों के पंजीयन के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अपील संबंधित विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक/विभाग प्रमुख को 90 दिवस में प्रस्तुत करना होगा।

स. अपील के निपटारे के संबंध में संबंधित विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक/विभाग प्रमुख द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम मान्य होगा।

द. अपील पर निर्णय की प्रति संबंधित अपीलीय प्राधिकारी निर्णय के तीन दिवस के भीतर राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को दी जाना होगी। इसके आधार पर राज्य पंजीकरण अधिकारी वेबसाइट पर ठेकेदार के पंजीयन की अद्यतन स्थिति दर्ज करेंगे।

इ. यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक से समस्त कार्य विभागों, निगम/मण्डल तथा बोर्ड में लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

7 MAY 2016

C.E. (I.S.)	S.E. (A)
C.E. (H.M.)	C.P.O.
C.E. (P)	E.E. (V)
S.E. (Major)	E.E. (D)
S.E. (W)	Sr. P.A.

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 3.05.2016

पृ. क्रमांक एफ 17-1/19/बी/2010 / 392.
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.आर.आर.डी.ए भोपाल।
6. प्रबंध संचालक पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन भोपाल।
7. आयुक्त, म.प्र. अधोसंरचना बोर्ड भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन भोपाल।
9. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई, निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
10. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग.....भोपाल।
11. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू भोपाल।
12. राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल।
13. आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

3/5/2016

114
11/5/16

4213
5E(B)
3/5/16

कार्यालय प्रमुख आभयता
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन
तलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

संख्या क्र. 42/30/79
प्रतिनिधि.

श्री. श्री. श्री.

01. मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
आवश्यक कार्यवाही हेतु अवेबिलिटी
02. जल संचालन विभाग
की ओर प्रस्तावना हेतु अवेबिलिटी


श्री. श्री. श्री.
अधीक्षक यंत्री (बजट)
जल संसाधन विभाग, भोपाल.